www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 24 जनवरी 2019

दैनिक जागरण
आत्मविश्वास से आत्मबल प्राप्त होता है

कांग्रेस का आखिरी दांव

प्रदीप सिंह

चूंकि प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा परिदृश्य में अपने आप जा जाते हैं इसलिए कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना संभव नहीं होगा

आखिरकार प्रियंका गांधी राजनीति में आ ही गईं। उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। क्या यह कांग्रेस का तुरुप का पत्ता है या हताशा में उठाया गया कदम? जो भी हो, प्रियंका अपने साथ अच्छा और बुरा दोनों लेकर आई हैं। उनके रूप में कांग्रेस को एक नया स्टार प्रचारक मिल गया है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा और वंशवाद का बैगेज भी लेकर आई हैं। प्रियंका के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी जानी है। उत्तर प्रदेश में अब तिकोना संघर्ष तय है। भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है। प्रियंका के आने से एक बात फिर से स्थापित हो गई है कि कांग्रेस परिवार की पार्टी थी, है और रहेगी।

लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले प्रियंका का सक्रिय राजनीति में आने के दो प्रमुख मकसद नजर आते हैं। एक, राहुल गांधी को कवर देने के लिए। अमेठी में राहुल गांधी की जमीन खिसक रही थी। ऐसी भी अटकलें हैं कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव न लड़ें, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल पर भारी पड़ती दिख रही थीं। दूसरा उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जा सके। कांग्रेस के नजरिये से यह रणनीति तो अच्छी है, लेकिन यह अभी साबित नहीं हुआ है कि प्रियंका चुनाव नतीजे को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। अभी दो साल पहले अमेठी और रायबरेली में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने डेढ़ दो महीने प्रचार किया, पर नतीजा सिफर ही रहा। इसके बावजूद यह मानना कि प्रियंका के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत होगा।

प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में उतारकर कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े राज्य में लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा धक्का सपा-बसपा गठबंधन को लगेगा, क्योंकि ये दोनों दल जिस लड़ाई को दो ध्रुवीय बनाकर जो लाभ लेना चाहते थे वह अब शायद संभव नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी ने सपा-बसपा के लिए अपना दरवाजा अभी बंद नहीं किया है। सबसे बड़ी समस्या अब मुस्लिम मतदाता के सामने होगी। उसे सपा-बसपा और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मुस्लिम मत के इसी बंटवारे का लाभ भाजपा को 2014 और 2017 में मिला था। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के जरिये सपा-बसपा को जवाब और धमकी दोनों दी है। अब इसकी प्रबल संभावना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सभी अस्सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे सपा-बसपा के बागियों को एक नया मंच मिल जाएगा और कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार, लेकिन उत्तर प्रदेश पूरा देश नहीं है। कांग्रेस के सामने बाकी राज्यों में जो समस्या है वह प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने से खत्म नहीं होने वाली। प्रियंका और ज्योतिरादित्य को उत्तर प्रदेश में उतारने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने जो कहा उससे लगता है कि उन्होंने दो कदम बढ़ाए तो हैं, लेकिन एक कदम पीछे आने को भी तैयार हैं। उन्होंने एक तरह से भाजपा से पहले सपा-बसपा को चेतावनी दी है कि हमें कम मत आंको। इसके साथ ही यह भी संकेत दिया है कि वह सपा-बसपा से हाथ मिलाने के लिए अब भी तैयार हैं। संदेश सीधा है कि हमें छोड़ा तो आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। अब गेंद मायावती और अखिलेश यादव के पाले में है। कहना कठिन है कि वे राहुल गांधी की इस चेतावनी से डरेंगे या अपने रुख पर कायम रहेंगे।

सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस कहां है? कोलकाता में ममता बनर्जी के मंच पर राहुल गांधी नहीं थे और बिहार में राजद खेमे में कांग्रेस के बिना गठबंधन के विकल्प पर भी विचार हो रहा है। यह भी देखें कि कांग्रेस जहां है वहां कोई और विपक्षी दल नहीं है। जी हां, कांग्रेस लंदन में है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को हैक किए जाने का फर्जी दावा अमेरिका से किया जा रहा था। ऐसा लगता है कांग्रेस खुद नहीं समझ पा रही है कि उसे कहां होना चाहिए और कहां नहीं? किसानों की कर्ज माफी पर उसने पूरे देश में हल्ला मचाया। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे सत्ता सौंप दी तो वह कर्ज माफी के जाल में उलझ गई है। उसने राफेल के मुद्दे को दूसरा बोफोर्स बनाने की कोशिश की, पर वह दिल्ली के लेफ्ट-लिबरल्स की बिरादरी के बाहर चल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पार्टी की उम्मीदों पर और पानी फेर दिया। इसके बाद अब कांग्रेस ने एक और पिटा हुआ मुद्दा उठाया है-ईवीएम मशीनों का। इसके लिए अमेरिका से एक नकाबपोश की लंदन में होने वाली प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल पहुंच गए। वहां से भारत के निर्वाचन आयोग पर हमला किया गया। इस नकाबपोश के सारे दावे फर्जी निकले, फिर भी सिब्बल साहब कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी 'बेबी'। इसमें भारत की खुफिया एजेंसी का मुखिया मंत्री से बार-बार कहता है कि विदेशी ऑपरेशन में यदि कोई गड़बड़ होती होती है तो हम कह देंगे कि यह (अक्षय कुमार, जो भारत के खुफिया एजेंट बने हैं) हमारा आदमी था ही नहीं। कांग्रेस पार्टी वैसा ही कुछ आजकल कपिल सिब्बल के साथ कर रही है। वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस कहती है, हमसे इसका कोई लेना-देना नहीं। लंदन में कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर भी कांग्रेस का यही जवाब है।

मोदी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस कहां है, समझना जरा कठिन है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से सीटों का तालमेल करेंगी? बिहार में कांग्रेस 16 सीटें मांग रही है। वह 12 से कम पर मानने को तैयार नहीं। उसकी मांग उसके गठबंधन से बाहर जाने का सबब बन सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी से किसी तरह के तालमेल की स्थिति नजर नहीं आती। क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस से हाथ मिलाएगी? सवाल यह भी है कि कांग्रेस के नए मित्र अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब और दिल्ली में साथ नजर आएंगे? कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में तालमेल का मुद्दा तय करने से पहले पार्टी के अंदर का असंतोष संभालना कठिन होता जा रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा अभी तक कहीं गठबंधन की तस्वीर साफ नजर नहीं आती। ऐसा लगता है मुद्दों के मोर्चे पर कोई खास कामयाबी न मिलने पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को सक्रिय करने का दांव खेला है। सवाल है कि क्या प्रियंका के आने भर से यह सब बदल जाएगा? क्या दूसरे विपक्षी दलों का कांग्रेस के प्रति नजरिया बदल जाएगा? चूंकि प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा परिदृश्य में अपने आप आ जाते हैं इसलिए कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना संभव नहीं होगा। कुछ भी हो, इतना तय है कि 2019 का चुनाव किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

भाई और बहन

केवल चुनावों के समय अमेठी और रायबरेली में राजनीतिक सक्रियता दिखाती रहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को यकायक कांग्रेस महासचिव बनाए जाने का फैसला चौंकाने वाला भले हो, लेकिन उसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। एक लंबे अर्से से यह कहा-माना जा रहा था कि वह राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए राजनीति में सक्रिय होंगी। आखिरकार वह न केवल महासचिव बनाई गईं, बल्कि उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार देकर यह बताने की भी कोशिश की गई कि वह हर तरह की राजनीतिक चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। एक लंबे वक्त बाद ऐसा पहली बार होगा जब नेहरू-गांधी परिवार के दो सदस्य एक साथ राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। भाई-बहन की राजनीतिक सक्रियता से कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति का जो नया रूप देखने को मिलेगा उससे पार्टी के भीतर के समीकरण भी बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने में हुई देरी के कारण प्रियंका के राजनीति में विधिवत प्रवेश में विलंब हुआ। जो भी हो, इसमें दो राय नहीं कि गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते ही वह सीधे कांग्रेस महासचिव बनने में सफल रहीं। यह तो साफ है कि उनके महासचिव बनने से परिवारवाद की राजनीति को बल मिला है, लेकिन यह समय बताएगा कि उनकी राजनीतिक सक्रियता कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में कितना सहायक बनेगी?

यह सही है कि प्रियंका के महासचिव बनने से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और चुनाव के दौरान वह भीड़ को आकर्षित भी करेंगी, लेकिन इसमें संदेह है कि उनकी इंदिरा जैसी कथित छवि उन्हें एक सफल नेता बनाने का काम करेगी। एक तो इंदिरा गांधी को गुजरे हुए अच्छा-खासा समय बीत गया और दूसरे आज का भारत नया भारत है। आज की पीढ़ी नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों के प्रति आकर्षित तो हो सकती है, लेकिन वह उनका अनुसरण तभी करेगी जब वे उसकी अपेक्षाओं को पूरा करते दिखेंगे। प्रियंका मुखर होने के साथ ही राजनीतिक मिजाज अवश्य रखती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच-समझ की असली परीक्षा होना अभी शेष है। निःसंदेह इसका पता भी आने वाले वक्त में ही चलेगा कि वह पति राबर्ट वाड्रा से जुड़े विवादों का सामना किस तरह करेंगी? बहन प्रियंका को महासचिव बनाने के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपकर राहुल गांधी ने यही स्पष्ट किया है कि वह उत्तर प्रदेश में वापसी करने को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर पर दो हिस्सों में बांटकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका को शायद इसीलिए दी ताकि कार्यकर्ताओं को यह संदेश जाए कि मोदी और योगी के गढ़ में कांग्रेस मुकाबले को तैयार है। वह केवल भाजपा के समक्ष ही चुनौती पेश करने नहीं दिख रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी यह संदेश दे रहे हैं कि वे उत्तर प्रदेश को अपने लिए खुला मैदान न समझें। यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे कांग्रेस दम-खम दिखाती है तो आम चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले की शक्ल ले सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन यह स्थिति भाजपा के लिए लाभदायक हो सकती है।

बदलाव का असर

यह सुखद संयोग है कि जिन राज्यों की विकास दर देश से ज्यादा है, उसमें बिहार भी शामिल है। वह भी ऐसी स्थिति में जब बंटवारे के बाद बिहार के हिस्से में खनिज नहीं आया। जिस राज्य झारखंड के हिस्से में खनिज संपदा गई, वहां संपन्नता की दर धीमी है। क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, केरल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की विकास दर धीमी है। यह देखना होगा कि खनिज संपन्न और स्थाई सरकार वाले छोटे राज्यों की विकास दर कम क्यों रह गई? बिहार ने जो बढ़त हासिल की है, उसमें निश्चय ही जमीनी स्तर पर हुए बदलाव का असर है। इस समय क्रियाशील सात निश्चय कार्यक्रम के कुछ भाग सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा है। रोजगार सृजन के लिए भी बिहार में जीविका और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से परिवर्तनकारी काम हुआ है। बिहार में कोई बड़ा उद्योग हाल के वर्षों में नहीं लगा है, लेकिन छोटे उद्यम में बेहतर इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11.3 फीसद के साथ बिहार की विकास दर देश में सबसे ज्यादा रही है। गत वर्ष देश की विकास दर 6.7 फीसद थी। हाल के दिनों में कृषि प्रवण बिहार में किसानी के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। विकास दर में वृद्धि बनाए रखने का एक माध्यम राजस्व की बढ़ोतरी है। बिहार ने शराब बंदी लागू कर उससे मिलने वाले राजस्व का नुकसान व्यापक हित में सहा है। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने सावधान भी किया है कि चुनावी साल में अगर राजनीतिक लोक लुभावन पॉलिसी अपनाई गई तो विकास दर की उच्चता पर पानी फिर सकता है। उन राज्यों को अगाह कराया गया है, जहां कृषि कर्ज माफी का स्वर मुखर है। बिहार अभी इन सबसे से परे है। यह अच्छी बात है कि बिहार के किसानों में कर्ज लेने की प्रवृत्ति काफी कम है। सरकार की फसल सहायता योजना में अनुदान की प्रक्रिया भी इस प्रकार की है, जिससे किसान बैंकों के कर्ज में बहुत नहीं फंसते हैं। बिहार को इसी रास्ते आगे बढ़ना होगा।

सामने आतीं विभाजन की गलतियां

आर विक्रम सिंह

देश विभाजन की जल्दबाजी में करतारपुर साहिब ही नहीं, हमारे बहुत से सूत्र उस पार छूट गए

करतारपुर साहिब गलियारे के लिए पाकिस्तान से बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर करतारपुर भारत का हिस्सा क्यों नही है? रावी और बसंतार नदियों के मध्य हमारी सीमा से मात्र पांच किमी दूरी पर स्थित सिखों के प्रथम गुरु नानकदेव जी की कर्मस्थली करतारपुर भारत का ही हिस्सा होता, यदि प्रधानमंत्री नेहरू ने 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच लॉर्ड मांउटबेटन से बल देकर इसके लिए कहा होता। ऐसा नहीं हो सका और आज हम वहां जाने के लिए गलियारा तलाश रहे हैं। आजादी से एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को जब जिन्ना के 'डायरेक्ट एक्शन' आह्वान से बंगाल में कत्लेआम हुआ तो हमारी अहिंसा के पास उसका कोई उपाय नहीं था। अहिंसक आंदोलन विधि शासित व्यवस्था के अन्याय के विरुद्ध कारगर हो सकता है, लेकिन हिंसा के खिलाफ नहीं। क्या हमारा अहिंसक आंदोलन ईदी अमीन, स्टालिन, माओ या हिटलर जैसे तानाशाहों के खिलाफ खड़ा भी हो पाता? यह जिन्ना की जिहाद के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो सका।

डेरा बाबा नानक एवं करतारपुर साहिब के बीच गलियारे का मुद्दा अटल जी ने भी अपनी लाहौर बस यात्रा के दौरान उठाया था। 1959 तक इस भूमि की अदला-बदली की बातें चल रही थीं, लेकिन बात बन नहीं पाई। यह जानना जरूरी है कि हमारी सीमाओं का निर्धारण कैसे हुआ। 8 जुलाई 1947 को सिरिल रेडक्लिफ भारत आए। उन पर मात्र पांच हफ्तों में भारत-पाकिस्तान की सीमाएं खींचने की जिम्मेदारी थी। पेशे से वकील रेडक्लिफ के सहयोग के लिए दो हिंदू और दो मुस्लिम सदस्य लगाए गए। उनका समय आपस में लड़ते हुए ही बीता। यह कवायद संदिग्ध तरीके से संपन्न हुई। अंतिम नक्शों को माउंटबेटन के हवाले कर शेष अभिलेख नष्ट कराने के बाद वह वापस लौट गए। हिंदू प्रतिनिधि जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह नक्शों के जानकार नहीं थे। प्रतीत होता है कि तब हमारे शीर्ष नेताओं ने सीमाओं के निर्धारण में खास रुचि नहीं ली।

पंजाब सीमा आयोग 30 जून, 1947 को गठित हुआ। उसे 15 अगस्त, 1947 तक रिपोर्ट देनी थी। उसके सदस्य थे, जस्टिस दीन मोहम्मद एवं मुहम्मद मुनीर। पहली बैठक 14 जुलाई को हुई। 18 जुलाई तक प्रत्येक पक्ष को अपना प्रस्ताव देना था। खुली सुनवाई 21 से 31 जुलाई तक लाहौर में पाकिस्तानी सदस्य दीन मोहम्मद की अध्यक्षता में हुई। तब रेडक्लिफ ढाका में बंगाल की सरहदें तय कर रहे थे। चमनलाल सीतलवाड़ ने कांग्रेस और हरनाम सिंह ने शिरोमणि अकाली दल का पक्ष प्रस्तुत किया। पाकिस्तानी पक्ष मात्र मुस्लिम आबादी की बहुलता के क्षेत्रों का तर्क दे रहा था। वहीं भारतीय पक्ष आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आधारों की दुहाई दे रहा था। 31 जुलाई को शिमला में आयोग के सदस्यों ने अपने-अपने नक्शे पेश किए। जस्टिस महाजन के नक्शे में बंसतार नदी को सीमा रेखा मानते हुए शंकरगढ़ को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। करतारपुर साहिब कस्बा और गुरुद्वारे को भारतीय क्षेत्र में लेते हुए नरावल कस्बे के दक्षिण में बसंतार-रावी संगम से आगे कुछ दूर तक वह रावी नदी के साथ प्रस्तावित सीमा को ले गए। अगर इस प्रस्ताव को अहमियत दी जाती तो करतारपुर साहिब भारतीय सीमा में आ जाता।

जस्टिस तेजा सिंह ने चिनाब नदी की सीमा प्रस्तावित की। फिर आगे वह जस्टिस महाजन के अनुसार ही चले। पाकिस्तानी पक्ष ने कोई नक्शा तो नही दिया, पर उसके लोगों ने मुस्लिम लीग की ही लाइन पकड़ी। वे पठानकोट, रोपड़, लुधियाना, फाजिल्का तक की मांग कर रहे थे। बहरहाल 12 अगस्त, 1947 को रेडक्लिफ ने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए अपनी रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब की सीमा तय हो गई। भारतीय पक्ष की पहल के बावजूद करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रह गया। माउंटबेटन ने घोषणा से पूर्व अनौपचारिक रूप से यह मानचित्र नेहरू को दिखाया था। वह गुरदासपुर के माध्यम से कश्मीर का मार्ग उपलब्ध हो जाने से संतुष्ट हो गए और शायद इसीलिए करतारपुर साहिब का बिंदु नेपथ्य में चला गया। पंडित नेहरू के स्तर से करतारपुर साहिब का समाधान होना बड़ा आसान था। वास्तव में हमारे नेताओं ने सीमाओं के निर्धारण को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि अच्छी-खासी हिंदू आबादी के बावजूद सिंध का विभाजन किए बिना ही उसे पूरा का पूरा जिन्ना को सौंप दिया। राजस्थान की सीमाओं पर स्थित सिंध के जिले उमरकोट एवं थरपाकर हिंदू बहुल थे। सिंधी समाज को सीधे-सीधे खारिज कर दिया गया जैसे वे भारत के भाग थे ही नहीं। जो सीमा आयोग बना वह मात्र पंजाब तक ही सीमित रह गया। उसका सिंध तक विस्तार नहीं हुआ।

आश्चर्य होता है कि हमारे नेताओं ने सिंध की अनदेखी क्यों की? हमारे नेताओं को यह भी ख्याल नहीं आया कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के जिस गीत को वे भारत का राष्ट्रगीत तय कर रहे है उसमें सिंध का नाम भी प्रमुखता से आता है। सिंधियों को पूरी तरह उनके भाग्य पर छोड़ देना दर्शाता है कि आजादी के अभियान के अंत तक हमारे नेताओं में वह जज्बा, वह शक्ति नहीं बची थी जिसके साथ 1920 से गांधी जी के नेतृत्व में उसका आगाज हुआ था। इसके चलते वह जो हमारा जिंदा इतिहास था उसके बहुत से सूत्र उस पार छूट गए है। असम तो खैर गोपीनाथ बारदोलाई के साहस से किसी तरह बच गया, लेकिन चटगांव हिल ट्रैक्ट के चकमा आदिवासी पाकिस्तानी त्रासदी के शिकार बन गए। आबादी में उनका हिस्सा 97 प्रतिशत था, लेकिन उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान से निकाली गई चकमा जनजाति की वह आबादी राज्यविहीन होकर बिना नागरिकता के अपना जीवन यापन करती रही। हाल में इस समाज को बड़ी राहत मिली है। अब वे भी गर्व से स्वयं को भारतीय कह पाएंगे।

बंगाल सीमा आयोग के समक्ष चटगांव हिल ट्रैक्ट के साथ चटगांव का दक्षिणी भाग काक्स बाजार का समुद्रतट जो आज म्यांमार की सीमाओं से मिलता है, मांगा जाना चाहिए था। मात्र 20 किमी चौड़ाई का सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही आज भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। पूर्वोत्तर के लिए आज कोई समुद्री बंदरगाह नहीं है। भारत का मजहबी बंटवारा अपने अंतिम चरण में खानापूर्ति जैसा था जिसमें न तो कोई आर्थिक विचार था, न सांस्कृतिक, न ऐतिहासिक। रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी सोच तो जैसे थी ही नहीं। तत्कालीन नेतृत्व की गैरजिम्मेदारियों ने हमें कश्मीर जैसी समस्या दी, 1962 की पराजय की टीस दी। करतारपुर गलियारा विभाजन की भूलों का प्रायश्चित है। भारत की विभाजित सीमाओं से गुजरना एक बड़ी त्रासदी से दो-चार होने जैसा है।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सर्वश्रेष्ठ पद

विचार करने से पता चलता है कि जो जिस समय से कुछ बनना प्रारंभ करता है, बस वहीं उसी क्षण उसके पीछे बिगड़ना लग जाता है। जैसे मनुष्य जन्म लेते ही मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है, पेड़ जब कुछ नहीं था तो मिट्टी था, जब वृक्ष बना तो मिटना भी पड़ेगा अर्थात कुछ बनना ही मिटना है। यदि हम न बनते तो मिटते क्या? तात्पर्य है कि जिसने जितनी उन्नति की, ठीक उतनी ही उसकी अवनति हुई। जल चाहे जितना गर्म कर दिया जाए अंत में शीतल ही हो जाता है। सबका आदि एवं अंत एक-सा है। अतः अपने वास्तविक रूप से जो जितना बढ़े हैं, वे उतनी ही अवनति कर चुके हैं। हम अपने देहाभिमान की बहुत उन्नति करवा रहे हैं। अभी तक हम अपने नाशवान कल्पित देहाभिमान को नहीं मिटाना चाहते तो हम सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं।

हमने जिसे नाश या अवनति समझा है वही वास्तविक उन्नति है, वही है परमपद। देहाभिमान को मिटाए बगैर स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता। अज्ञान का ही यह प्रभाव है कि हम सभी पूर्ण हैं। फिर भी शरीर बने बैठे हैं। हम शरीराभिमान रखते हुए पूर्ण होना चाहते हैं। बहुत सुखी व्यक्ति और कुछ चाहेगा तो दुखी ही होगा। सुखी का कुछ चाहना ही दुख चाहना सिद्ध करता है। जैसे बुलबुले जल की इच्छा रखते हुए भी बुलबुले हैं, जबकि बुलबुले जल ही हैं, लेकिन उन्हें फूटने का डर बना ही रहता है और अंत में फूटकर उन्हें जल ही होना पड़ा। अपने बुलबुले के अस्तित्व को मिटाना पड़ा। वहीं जिन बुलबुलों ने पहले ही निश्चय कर लिया कि हम जल हैं, वे भी उसी जल में मिले, परंतु अमर होकर हंस-हंसकर।

आज तक हम बहुत बढ़ते रहे, परंतु कुछ भी न बढ़ सके और न पीछे लौट सके। हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सका। फिर चिंता किस बात की है। इस प्रकार निश्चिंत होना ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वसिद्ध पद या परम पद है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना है। कुछ बनना या मिटना नहीं है। हम बन भी नहीं सकते। यह हमेशा हमारे पास रहा है और रहेगा। वास्तव में यही आत्म-पद या परम पद अथवा सर्वश्रेष्ठ पद है। इसकी अनुभूति करके ही जीवन के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया जा सकता है और जीवन को वास्तविक रूप से सार्थक बनाया जा सकता है।

अवधविहारी शुक्ल

दुर्लभ बीमारियों के उपचार में सुस्ती

ंजीत सिंह

्र्लभ बीमारियों से लड़ने में नाकाम 21 महीने ी आशान ने एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी ी वजह से राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दम तोड़ दिया। ससे घबराकर परिवार ने अपने बेटे के उपचार ी अपील में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन खबर है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ंत्रालय ने इसे अनसुना कर दिया। देश में यह कलौता ऐसा मामला नहीं है। मरीज दम तोड़ रहे ँ, क्योंकि सरकार दुर्लभ बीमारियों के इलाज की ॉलिसी के मामले में चुप्पी साधे बैठी है। दुर्लभ ीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति को वीकृत हुए अब तक 78 हफ्ते से भी ज्यादा ामय बीत चुका है, लेकिन अभी भी मरीजों को सके अमल में आने का इंतजार है। इस इंतजार ों 20 से भी ज्यादा बच्चे जान गंवा चुके हैं।

जो नीति दुर्लभ बीमारियों के मामले में लोगों े लिए राहत की तरह आई, अब लगातार केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरशाही के बीच लझकर रह गई है। भारतीय राज्यों में उपचार ी पहल को लागू करने के लिए उपयुक्त कानूनी स्तक्षेप के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं

दुर्लभ
लिए र
लागू क
जरूर

आता। इस 100
करोड़ रुपय ोने पर
यह पिछले खत्म
हो गया। य
आवेदनों क
शुरू करने
जैसे-सेंटर
टेक्निकल
सेल की स , लेकिन लगता
नहीं है कि ो इलाज मिलने
की प्रक्रिया
आवेदन ल जटिलताओं
को बढ़ा रह रवार को सबसे
पहले सीधे संबंधित राज्य
स्वास्थ्य अ रना होता है। उस
आवेदन क जाता है, जरूरी
समीक्षा के भेज दिया जाता

है। ि (60:40 अनुपात)
के अ ा में भेज दिया जाता
है, ज करती है। इस लंबी
प्रक्रि ुरू किया जा सकता
है। य पिछले 17 महीनों
में ए लिए नामांकित या
स्वी ेश से स्वास्थ्य एवं
परि ों रेयर डिजीज सेल
द्वारा कोई भी प्रगति नहीं
हुई ह ोदनों की प्रक्रिया को
लब्ध कराने के लिए
पना वक्त ले रही है।
खत्म होता जा रहा है।
रियों को स्वास्थ्य
हचानने की जरूरत
है। इसे केवल यह कहकर खारिज नहीं कर सकते कि यह 'कुछ लोगों' को ही प्रभावित करती है। जाहिर है इसके लिए तेज प्रक्रिया और दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति को लागू करने की बेहद जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें तथा उससे जुड़े हितधारकों के लिए एक साथ मिलकर दुर्लभ बीमारियों को हराने का समय आ गया है।

(लेखक एलएसडीएस के प्रेसिडेंट हैं)

विदेशी धरती पर ईवीएम हैकिंग का तमाशा

राजीव सचान ने अपने आलेख 'सामान्य समझदारी की हैकिंग' में ईवीएम हैकिंग के झूठ का पर्दाफाश करते हुए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के सहयोग से लंदन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सैयद शुजा नाम के किसी तकनीशियन के माध्यम से भारत में चुनाव के समय प्रयुक्त होने वाली ईवीएम हैकिंग के जिस हास्यास्पद तमाशे का जिक्र किया है, वह चौंकाने वाला है। भारत के अंदर जिस ईवीएम के द्वारा लोकतांत्रिक चुनाव को संपन्न किया जाता है, उसको लंदन की एक प्रेस कांफ्रेंस में संदिग्ध बताना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। भारतीय ईवीएम को बदनाम करने वाली इस विदेशी कांफ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आम चुनाव से पूर्व भारत के चुनाव में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम को हैकिंग की संभावना से ग्रस्त बताना इस देश की विकृत राजनीति का वह हिस्सा है जो भारत के मान-सम्मान की चिंता नहीं करती। विपक्ष में बैठने की पीड़ा से ग्रस्त कांग्रेस ईवीएम को लेकर इस तरह की स्तरहीन और घटिया राजनीति करने को आज इसलिए विवश है, क्योंकि उसे 2019 के आम चुनाव में अपनी हार का पूर्वाभास होने लगा है। शायद इसीलिए अपनी भावी हार का ठीकरा चुनाव में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम हैकिंग पर फोड़ने के उद्देश्य से वह लंदन में भारतीय ईवीएम हैकिंग का तमाशा खड़ा करने में सहयोगी बनी है, लेकिन अपने निहित स्वार्थ में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बात को भूल बैठी कि विदेशी धरती पर ईवीएम हैकिंग की बात करने से वह उस महान भारतीय लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है जिसके बल पर उसे अभी हाल में भारत के तीन बड़े राज्यों के चुनाव में जीत हासिल हुई है। बावजूद इसके यदि जीत का अनूठा स्वाद चखाने वाली उसी ईवीएम को कांग्रेस अब फिर से अविश्वसनीय मानने लगी है तो बेहतर होता कि उसका परीक्षण लंदन में प्रायोजित कराने की अपेक्षा अपने ही देश में उसकी जांच कराने का प्रयास करती।

डॉ. विष्णु प्रकाश पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

एक भारत, श्रेष्ठ भारत

देश के राजनीतिक हालात देखकर नहीं लगता कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद हो सकेगा। एक भारत बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिज्ञों के सुर और सोच एकमत नहीं दिख रही। कुछ दलों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाने में भी संकोच होता है। कथित राष्ट्र-प्रेमी लोगों की स्थिति यह है कि ये लोग भारत माता की जय कहना भी उचित नहीं समझते। भला किसी सच्चे भारतीय को भारत माता की जय बोलने में कोई तकलीफ हो सकती है? ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

निरर्थक बहस

विपक्ष वर्तमान केंद्र सरकार के पीछे ईवीएम का डर दिखाकर सत्ता पाने की जुगाड़ में है। इसी चक्कर में महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे के निधन का प्रकरण भी उछल गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते थे और उनके निधन का कारण एक साधारण सड़क दुर्घटना बताई गई थी। बात सही हो या गलत, मुद्दा तो बन ही जाता है। अभी उप्र सरकार ने साधु-संतों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, लेकिन इससे पहले उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा और साधु-संतों की परिभाषा भी तय करनी होगी, क्योंकि माथे पर टीके और भगवा वस्त्र पहन लेने मात्र से ही कोई साधु संत नहीं बन जाता। ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक सभी मंदिरों का पंजीकरण और उनमें पूजापाठ करते पुजारियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी शैक्षिक योग्यता को सूचीबद्ध करके और मंदिरों के आय-व्यय के साथ दान में मिले पैसे का पूरा ब्योरा भी एक पोर्टल पर डालना होगा और यह काम इतना सरल नहीं है।

rachnarastogi66@gmail.com

आयकर वसूली

देश में आज भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो घरों के सामने कार, दो नंबर का व्यापार और गरीबों पर आर्थि
सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं भर सकते।
देखने में आता है कि बड़े करदाता ही टैक
खोजते हैं और आय छिपाते हैं। आयकर
कर वसूली के पुख्ता उपाय करने होंगे।

ि

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्य
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर ्
करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित
भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेज
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्क
डी-210-211, सेक्टर-63,
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संप
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961
दकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
20-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।